

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -985/2014/कोटा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुरअपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लि. कोटा

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम.एल. पाटौदी
अभिभाषक।

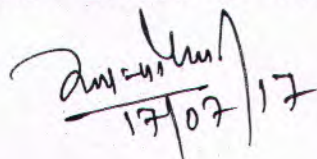
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 17.07.2017

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 84/वैट/2012-13/कोटा में पारित आदेश दिनांक 11.11.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट-द्वितीय, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) ने दिनांक 01.10.2012 को वाहन संख्या के.ए.01बी-2408, पांडीचेरी से चितोडगढ़ आते हुए गोरधन विजास रोड, उदयपुर में चैक किया गया वाहन में आयरन स्ट्रक्चर एवं पाईप का परिवहन किया जा रहा था। परिवहन माल के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा इनवाइस, बिल्टी एवं फार्म जेजे पेश किये गये। परिवहनित माल के साथ फार्म वेट-47 नहीं पेश किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल को अधिसूचित श्रेणी का मानते हुए परिवहनित माल के साथ आवश्यक दस्तावेज वेट-47 न होने के कारण इसे अधिनियम की धारा 76(2) को उल्लंघन माना तथा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी फर्म के कर्मचारी श्री शिशुपाल ने कम्पनी की ओर से लिखित जवाब पेश करते हुए रिक्त वेट-47 पेश किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रस्तुत वेट 47 को अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत माल की कीमत 12,52,710/- की 30 प्रतिशत शास्ति रू0 3,75,813/- अधिरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय

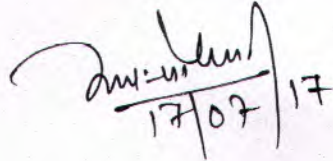
लगातार.....2.


17/07/17

अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी. मेटल्स के आलोक में आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्षों की बहस सुनी गई।
4. बहस के दौरान राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.11.2013 का खण्डन करते हुए कथन किया कि परिवहनित माल "आयरन स्ट्रक्चर एवं पाईप" अधिसूचित श्रेणी की वस्तु है, जिसके परिवहन के दौरान घोषण पत्र वेट-47 होना आज्ञापक है। जांच के दौरान वाहन चालक द्वारा घोषणा प्रपत्र वेट-47 प्रस्तुत नहीं किया गया व प्रत्यर्थी फर्म द्वारा अपने जवाब के साथ रिक्त घोषण पत्र वेट-47 पेश किया गया, जो कि अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था, जिससे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर दिया गया, जो की विधि विरुद्ध है। राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक अपने इस कथन के साथ निवेदन किया कि राजस्व की अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.11.2013 को निरस्त की जाये।
5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्थी एक ठेकेदार है। प्रत्यर्थी द्वारा पांडीचेरी साईड से चित्तौडगढ़ की साईड पर कनस्ट्रेशन के काम में आना वाला सामान परिवहनित किया गया था। न कि विक्रय या स्टॉक ट्रांसफर किया था। अतः इस माल पर वेट-47 की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे विक्रय मानते हुए वेट-47 की अनिवार्यता मानते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है जो अविधिक था। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों की सही व्याख्या करते हुए व विधिक प्रावधानों के अनुकूल आदेश पारित किया है इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपने इस कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अपीलीय आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक द्वारा मैसर्स डी.पी. मेटल्स 124 एस.टी.सी. 611 एवं मैसर्स शोरा टैक इण्डिया बनाम ए.सी.टी.ओ भिवाडी के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।
6. उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मन अध्ययन किया गया।
7. विभागीय पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा पांडीचेरी से चित्तौडगढ़ जो आयरन स्ट्रक्चर एवं पाईप परिवहनित किया गया। वक्त चैंकिंग वाहन चालक द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। परिवहनित माल

लगातार.....3.


17/07/17

अधिसूचित श्रेणी का था तथा उसके साथ प्रारूप वैट-47 नहीं पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी फर्म को अधिनियम की धारा 76(2) के नियम 53 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में फर्म के द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा लिखित जवाब पेश करते हुए वैट-47 पेश किया गया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार करते हुए शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी. मेटल्स 124 एस.टी.सी. 611 के आलोक में, आरोपित शास्ति अपास्त की गई।

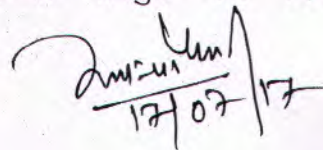
8. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत (2001) 124 एस.टी.सी. 611 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम डी.पी. मेटल्स में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"..... Once the ingredients of section 78(5) are established, after giving a hearing and complying with the principles of natural justice, there is no discretion not to levy or levy lesser amount of penalty. If by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking principles of natural justice may require some opportunity being given to produce the same."

न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी. मेटल्स 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का मैसर्स शेर टैक इण्डिया बनाम ए.सी.टी.ओ भिवाडी S.B. Sales Tax Revision Petition No. 190/2012 निर्णय दिनांक 07.01.2013 के मामले में अनुसरण किया गया जिसके सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है:-

"The Hon'ble supreme court of India in case of D.P. metals (supra) has categorically held that on show cause notice regard to alleged contravention/deficiency found in a respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case it is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by the themselves indicative of the bonafides of the transit of the goods. Following in the case of DP metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day petitioner assessee having furnished form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under section 76(6) of the RVAT Act."

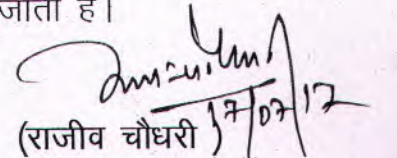
9. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ वैट-47 प्रस्तुत कर दिया गया था। अतः उपरोक्त

 17/07/17

लगातार.....4.

उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों मैसर्स डी.पी. मैटल्स 124 एस.टी.सी. 611 एवं मैसर्स शोरा टैक इण्डिया बनाम ए.सी.टी.ओ भिवाडी में प्रतिपादित सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण पर चस्पा होते हैं जिसमें व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ घोषणा पत्र वेट-47 प्रस्तुत कर दिये जाने से धारा 76 में कोई उल्लंघन कारित नहीं किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 11.11.2013 को पारित करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई है। प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में वर्तमान प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं उचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 11.11.2013 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

10. परिणामस्वरूप उक्त अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2013 की पुष्टि करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
11. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी) 17/02/12
सदस्य